पांडुरंग, तुकिया और भिल्लिया

बनाम

हैदराबाद राज्य

[मुखर्जी, एस.आर. दास और विवियन बोस जे.जे.]

भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम XLV), धारा 34-पूर्ववर्ती सामान्य उद्देश्य -एक ही या समान उद्देश्य -दोनों के बीच अंतर।

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में सामान्य इरादा क्योंकि पूर्व-निर्धारित योजना का अनुमान लगाता है। इसके लिए एक पूर्व नियोजित योजना की आवश्यकता होती है क्योंकि इससे पहले कि किसी व्यक्ति को दूसरे के आपराधिक कृत्य के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दोषी ठहराया जा सके, यह कार्य उन सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया होगा। तदनुसार मस्तिष्क की एक पूर्व बैठक होनी चाहिए थी। कई व्यक्ति एक साथ एक व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं और प्रत्येक का एक ही इरादा हो सकता है, अर्थात् मारने का इरादा, और प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से एक अलग घातक प्रहार कर सकता है और फिर भी किसी का भी अनुभाग द्वारा आवश्यक सामान्य इरादा नहीं होगा क्योंकि पूर्व-निर्धारित योजना बनाने के लिए मस्तिष्क की एक पूर्व बैठक नहीं थी। इस तरह के मामले में, प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा की गई किसी भी चोट के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, लेकिन किसी को भी अन्य के किसी भी कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और यदि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सकता है कि उसका अलग प्रहार घातक था तो उसे हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है,

हालांकि स्पष्ट रूप से उसके मामले में हत्या करने का इरादा साबित किया जा सकता है।

इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक ही या समान इरादे को समान इरादे के साथ भ्रमित न किया जाए; विभाजन जो उनकी सीमाओं को विभाजित करता है, अक्सर बहुत कम होता है, फिर भी अंतर वास्तविक और पर्याप्त होता है, और अगर अनदेखी की जाती है तो इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी। योजना को विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है, न ही लंबे समय के अंतराल की आवश्यकता है। यह अचानक उत्पन्न हो सकता है और बन सकता है। लेकिन पूर्व व्यवस्था और पूर्व नियोजित कार्यक्रम होना चाहिए। एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से एक ही इरादा रखना पर्याप्त नहीं है।

सामान्य इरादे के निष्कर्ष पर तब तक नहीं पहुंचना चाहिए जब तक कि यह मामले की परिस्थितियों से अनुमानित एक आवश्यक निष्कर्ष न हो। यह हर मामले में तथ्य का सवाल है और परिस्थितियों के समान होने के बावजूद, एक मामले में तथ्यों का उपयोग दूसरे मामले में तथ्यों पर निष्कर्ष निर्धारित करने के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं किया जा सकता है। केवल इतना आवश्यक है कि या तो पूर्व संयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण हो, या उन परिस्थितियों का प्रमाण हो जो आवश्यक रूप से उस निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं, या, दूसरे शब्दों में, दोषारोपण करने वाले तथ्य अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होने चाहिए और किसी अन्य उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होने चाहिए। जब अपीलीय न्यायाधीश, जो अपराध के सवाल पर सहमत होते हैं, सजा के बारे में अलग-अलग होते हैं, तो आम तौर पर मृत्युदंड नहीं दिया जाता है जब तक कि कोई ठोस कारण न हों।

बरेंद्र कुमार घोष बनाम राजा-सम्राट ([1924] एल. आर. 52 आई. ए. 40), महबूब शाह बनाम राजा-सम्राट ([1945] एल. आर. 72 आई. ए. 148) और मामंद बनाम सम्राट (ए. एल. आर. 1946 पी. सी. 45) का उल्लेख किया गया है।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार:-1954 की आपराधिक अपील संख्या 91 से 93 तक।

उच्चतम न्यायालय द्वारा 18 जनवरी, 1954 को हैदराबाद उच्च न्यायालय के 18 जून, 1953 के निर्णय और आदेश से पुष्टि केस संख्या 376/6 और आपराधिक अपील संख्या 394/6,395/6 और सत्र केस संख्या 9/8 में बीदर में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के 2 जून, 1952 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न केस संख्या 392/6 में विशेष अनुमति द्वारा अपील की गई।

अपीलार्थी की ओर से (1954 की आपराधिक अपील संख्या 91 में) जे. बी. दादाचंजी और राजिंदर नारायण।

अपीलार्थियों के लिए (1954 की आपराधिक अपील संख्या 92 और 93 में) एन. सी. चक्रवर्ती।

प्रतिवादी की ओर से पी. ए. मेहता और पी. जी. गोखले।

3 दिसंबर 1954

न्यायालय का निर्णय जे. बोस द्वारा दिया गया था।

तीन अपीलार्थियों सहित पाँच व्यक्तियों पर एक रामचंद्र शेल्के की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया था। प्रत्येक को दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय में अपीलों और पुष्टि की कार्यवाही की सुनवाई एम. एस. अली खान और वी. आर. देशपांडे, जे. जे.

द्वारा की गई। वे अलग थे। पूर्व ने विचार किया कि दोषसिद्धि को बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन उनकी राय थी कि प्रत्येक मामले में सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाना चाहिए। बाद वाले ने सभी पांचों मामलों में बरी होने का पक्ष लिया। तदनुसार मामला तीसरे न्यायाधीश, पी. जे. रेड्डी, जे. के पास भेजा गया था, उन्होंने दोषसिद्धि के बारे में पहले से सहमति व्यक्त की और सभी पांचों को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। सजा के सवाल पर उन्होंने विचार किया कि तीन अपीलार्थियों, पांडुरंग, तुकिया और भिलिया की मौत की सजा बरकरार रखी जानी चाहिए और अन्य दो की मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरे न्यायाधीश की राय को न्यायालय के निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया और इसलिए उनके द्वारा सुझाए गए वाक्यों के साथ-साथ दोषसिद्धि को भी बनाए रखा गया। इसके बाद सभी पांचों दोषियों ने अपील करने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया। याचिका की सुनवाई अली खान और रेड्डी, जे. जे. ने की और उन्होंने निम्नलिखित आदेश दियाः "इस मामले में अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि एक क्रूर हत्या की गई थी और सत्र न्यायाधीश के लिए मौत की सजा ही कानूनी रूप से संभव थी और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।"

अपील करने की अनुमति से इनकार कर दिया गया। पांडुरंग, तुकिया और भिलिया, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, उन्होंने अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए यहां आवेदन किया। उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई। अन्य दो ने अपील नहीं की है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 7.12.1950 को लगभग दोपहर के तीन बजे रामचंद्र शेल्के (मृतक) अपनी पत्नी की बहन रसिका बाई (पी. डब्ल्यू. 1) और अपनी नौकर सुभाना राव (पी. डब्ल्यू. 7) के साथ "भावरा" नामक अपने खेत में गया। रसिका बाई ने खेत में मिर्च चुनना शुरू कर दिया जबकि रामचंद्र

दूसरे खेत "वनिया-चे-सेठ" में चला गया जो लगभग एक फरलोंग दूर है। हम समझते हैं कि यह क्षेत्र पापाना नामक नदी के पास है। वैसे भी, रसिका बाई ने उस दिशा से चिल्लाने की आवाज सुनी, इसलिए वह सुभाना के साथ नदी के किनारे तक दौड़ी और वे दोनों कहते हैं कि उन्होंने सभी पांचों अभियुक्तों को रामचंद्र पर कुल्हाड़ियों और डंडों से हमला करते देखा।

पड़ोस में मौजूद दो अन्य व्यक्ति, लक्ष्मण (पीडब्लू 6) और एल्बा (पीडब्लू 5) भी रोने की आवाज सुनकर मौके पर भाग गए। वे यह भी कहते हैं कि उन्होंने हमले को देखा और सभी पांचों अभियुक्तों के नाम बताए। पहले वाले के पास एक खेत है और वह उसमें काम कर रहा था। रसिका बाई ने हमलावरों को रामचंद्र को न पीटने के लिए चिल्लाया, लेकिन उन्होंने उसे धमकी दी और फिर भाग गए। रामचंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। चार चश्मदीद गवाह हैं, और मुख्य सवाल जिस पर हमें विचार करना है वह यह है कि क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है। आम तौर पर, हम तथ्य के प्रश्नों की जांच नहीं करते, लेकिन चूंकि तीन व्यक्तियों को तीसरे न्यायाधीश की राय पर मौत की सजा सुनाई गई है, एक की राय के बावजूद कि मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए और दूसरे की राय के बावजूद कि अपीलार्थी दोषी नहीं हैं और इसलिए उन्हें बरी कर दिया जाना चाहिए, हमने साक्ष्य की जांच करना उचित समझा है। दो चश्मदीद गवाहों को रेड्डी, जे. द्वारा उच्च न्यायालय में अविश्वसनीय माना गया था, इसलिए हम उन्हें विचार से हटा देंगे और अन्य दो, रसिका बाई (पीडब्ल्यू 1) और सुभाना (पीडब्ल्यू 7) पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोनों ने हमले के बारे में जो देखा उसका काफी हद तक एक ही संस्करण दिया। उन्होंने नदी के किनारे की दिशा से रामचंद्र के चिल्लाने की आवाज सुनी और वहाँ भाग गए। उनका कहना है कि उन्होंने सभी पांचों अभियुक्तों को उसे, तीन अपीलकर्ताओं पांडुरंग, तुकिया और भिलिया को कुल्हाड़ियों से, और अन्य दो, जिन्होंने अपील नहीं की है, को डंडों से मारते देखा। ऐसा कहा जाता है कि जिस आदेश

में क्रम किए गए थे और उनकी संख्या के बारे में रसिका बाई के सत्र न्यायालय और सत्र और समादेशित न्यायालय में दिए गए बयान के बीच कुछ विसंगति है। अली खान, जे. और रेड्डी, जे. ने इसे महत्वहीन माना और और ऐसा ही हमने भी। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों गवाह निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमत हैं।

(1) उस तुकिया ने रामचंद्र के गाल पर वार किया; रसिका बाई ने आगे कहा कि उसने उसके सिर पर भी वार किया;

(2) पांडुरंग ने उसके सिर पर वार किया;

(3) इन प्रहारों के बाद रामचंद्र नीचे गिर गया और फिर भीलिया ने उसकी गर्दन पर वार किया। सुभाना ने यह नहीं कहा कि अन्य दोनों ने कोई विशेष प्रहार किया। रसिका का कहना है कि उनमें से एक, नीलिया, रामचंद्र को अपनी छड़ी से जांघ पर मारता है और दूसरे को कोई विशेष प्रहार नहीं देता है।रसिका बाई का कहना है कि हमले को देखकर उसने आरोपी को नहीं मारने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने "अपनी कुल्हाड़ी और डंडे उठाए" और उसे धमकी दी, और फिर भाग गए। सुभाना केवल इतना कहती है कि वे भाग गए। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। उन्हें अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया गया और अलग-अलग मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया गया। प्रत्येक के मामले में क्रमशः गिरफ्तारी और समर्पण की तारीखें इस प्रकार हैंः -भिलिया 9-1-1951 और 14-6-1951 तुकिया 13-10-1951 और 10-1-1952 पांडुरंग 31-8-1951 और 10-1-1952 तुकाराम 13-4-1951 और 29-9-1951नीलिया 13-10-1951 और 10-1-1952 इस साक्ष्य पर मुख्य हमला इस तथ्य पर किया गया था कि न तो आरोपी और न ही चश्मदीद गवाहों का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रिपोर्ट निम्नलिखित परिस्थितियों में बनाई गई थी।

रसिका और सुभाना का कहना है कि हमले के बाद वे वापस गाँव चले गए और रसिका की बहन नरसाबाई, पी. डब्ल्यू. 2 (मृतक की विधवा) को बताया कि उन्होंने क्या देखा था। नरसाबाई का कहना है कि उन्होंने उस समय हमलावरों के नामों का खुलासा किया। यहाँ से हम पुलिस पटेल के पास जाते हैं जो एक मील दूर पड़ोसी गाँव में रहता है। वे महादप्पा (पीडब्लू 9) हैं। वह कहता है कि वह अपने ही गाँव में अपने घर के बाहर खड़ा था जब सूरज डूब रहा था और उसने मृतक की सास कृष्णबाई को रोते हुए देखा, जब वह उसके घर के बाहर से गुजर रही थी। उसने उससे पूछा कि क्या गलत था और उसने उसे बताया कि उसके दामाद की हत्या कर दी गई है। यह सुनकर उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, एक्स नंबर 4, और इसे उदगीर के पुलिस स्टेशन में भेज दिया जो हत्या के स्थल से लगभग छह मील दूर है। इस रिपोर्ट के आधार पर अगली सुबह 10 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

अब कोई नहीं बताता कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कौन ले गया। यह एक मुद्रित रूप में लिखा गया है और पुलिस पटेल द्वारा हस्ताक्षरित है। "शिकायतकर्ता या मुखबिर का नाम और पता" शीर्षक वाले कॉलम के सामने "तुकाराम पुत्र पांडा श्योलका" दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने वाले उप-निरीक्षक ने इसमें निम्नलिखित दर्ज कियाः

"मुझे प्रस्तुत करना है कि आज पुलिस पटेल, नीमगांव गाँव से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि (1) तुकाराम, पुत्र पांडा श्योलका, नीमगांव गाँव के निवासी, आए और कहा कि रामचंद्र पुत्र गोविंद रेड्डी की हत्या कर दी गई थी, आदि। पुलिस पटेल हमें बताता है कि यह तुकाराम मृतक का चचेरा भाई है। वह यह भी कहता है कि-"तुकाराम, जिसका नाम कॉलम नंबर 2 में दर्ज है, सूचना देने वाला नहीं है, बल्कि इस मामले में शिकायतकर्ता है। तुकाराम ने मुझे कोई लिखित शिकायत नहीं दी थी। उन्होंने मुझे मौखिक जानकारी नहीं दी थी। जब मैंने कृष्णबाई को रोते और

जाते देखा, तो मुझे नहीं पता था कि तुकाराम कहाँ हैं। मुझे नहीं पता कि उस दिन तुकाराम गाँव में मौजूद थे या नहीं।

इससे मामला रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन तथ्य यह है कि रिपोर्ट बनाई गई थी, हमें लगता है कि यह भी विवाद से परे है कि यह अगली सुबह लगभग 10 बजे बनाई गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि उपनिरीक्षक यह नहीं कहते हैं कि तुकाराम उनके पास रिपोर्ट लाए थे, बल्कि वह एक्स-4 (पुलिस पटेल से प्राप्त रिपोर्ट) में कहा गया है कि तुकाराम ने पुलिस पटेल को जानकारी दी थी। इसमें वह सही नहीं है (हालांकि गलती काफी स्वाभाविक है), क्योंकि एक्स-4 केवल तुकाराम का नाम मुद्रित कॉलम के सामने रखता है जिसका शीर्षक "शिकायतकर्ता या सूचना देने वाला" है इससे मामला संदिग्ध हो जाता है, लेकिन पुलिस पटेल हमें जो बताती है, उसे देखते हुए हमें लगता है कि उसका मतलब यह बताना था कि तुकाराम शिकायतकर्ता था, शायद इसलिए कि वह एक महिला का नाम दर्ज नहीं करना चाहता था और इसलिए उसने निकटतम पुरुष रिश्तेदार को चुना। हम उनके बयान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। उनका कहना है कि वह उस समय किसी का नाम नहीं जानते थे और यह रिपोर्ट से स्पष्ट है। लेकिन अपीलार्थियों के विद्वान वकील का कहना है कि उसने नरसाबाई को हत्या की शाम को देखा था और क्योंकि उसने उसे कोई नाम नहीं दिया था, यह स्पष्ट है कि कोई नहीं जानता था कि हमलावर कौन थे और इसलिए आरोपी के खिलाफ लगाया गया आरोप बाद की साजिश थी और यही कारण था कि उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना देने से पहले अगली सुबह तक इंतजार किया।

पुलिस पटेल महादप्पा स्वीकार करते हैं कि वह उसी रात घटना स्थल पर गए थे और वह पूरी रात वहीं रहे। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसने वहाँ नरसाबाई को देखा था लेकिन कहता है कि उसने उससे बात नहीं की थी। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे हमलावरों के नाम तब पता चले जब वह वहाँ गया था, लेकिन यह

उसकी रिपोर्ट भेजने के बाद हुआ था। रिपोर्ट के बारे में कुछ रहस्य है। यह अगले दिन सुबह 10 बजे तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा, हालांकि इससे पहले शाम को सूर्यास्त के बारे में लिखा गया था, लेकिन हम नहीं जानते कि इसे किसने लिया और उसने देरी क्यों की, यह अटकलें लगाना व्यर्थ है। यह निश्चित है कि अगर देरी का विचार एक कहानी गढ़ने और निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने का था तो अगली सुबह बिना नाम के रिपोर्ट भेजने का कोई मतलब नहीं था। वे या तो तब तक नामों पर प्रहार कर चुके होंगे या तब तक थोड़ा और इंतजार करेंगे जब तक कि वे उस कहानी के बारे में अपना मन नहीं बना लेते जिसे वे बताना चाहते थे। जिस अव्यवस्थित तरीके से रिपोर्ट लिखी गई और भेजी गई, वह चतुर और सुनियोजित छल के बजाय देहाती सादगी को दर्शाता है। यह याद रखना चाहिए कि मृतक ने इस चचेरे भाई तुकाराम के अलावा कोई पुरुष रिश्तेदार नहीं छोड़ा, जिसके बारे में पुलिस पटेल बात करते हैं, और उसके पिता पांडु, और हालांकि रामचं और तीन अपीलार्थियों के बीच दुश्मनी का खुलासा किया गया है, इस तुकाराम या उसके पिता पांडु को झगड़े से जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है; और कोई भी यह नहीं कहता है कि किसी और को उनसे कोई शिकायत थी।

हमें लगता है कि यह संभावना नहीं है कि ये तीन महिलाएं, रसिका बाई, नरसाबाई और कृष्णबाई, इस विस्तृत कहानी को गढ़ने और पुलिस पटेल को प्रभावित करने में सक्षम होतीं, जब तक कि वे एक उपयुक्त कहानी के बारे में नहीं सोचती और अपनी साजिश के लिए संभावित पीड़ितों को नहीं ढूंढ लेती। इसके अलावा, खबर फैलते ही शायद पूरा गाँव बाहर निकल गया; किसी भी मामले में गवाह इस बात से सहमत हैं कि वहाँ एक बड़ी भीड़ थी। हमें लगता है कि कई लोगों को यह कहना आसान होता कि हालांकि उन्होंने रसिकाबाई, सुभाना और नरसाबाई और अन्य उपस्थित लोगों से उन्हें यह बताने के लिए कहा कि क्या हुआ था, लेकिन कोई नहीं बता सका क्योंकि कोई नहीं जानता था। यह मान लेना हास्यास्पद होगा कि पूरा गाँव अभियुक्तों से घृणा करता

था और उनके खिलाफ एक विस्तृत साजिश में शामिल हो गया। इन परिस्थितियों में, हमें लगता है कि महादप्पा ने सच कहा। इसलिए रिपोर्ट में नामों की अनुपस्थिति इस मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जांच के समय नामों का पूरा खुलासा किया गया था। इस बारे में बोलने वाले सभी गवाह इस बात पर सहमत हैं। एक बार जब उस बाधा को पार कर लिया जाता है, तो रसिकाबाई और सुभाना के साक्ष्य में आलोचना करने के लिए बहुत कम है, गैर-महत्वपूर्ण विसंगतियों और इस तथ्य को छोड़ दें कि उन्होंने अदालत में अपनी गवाही और उनके पहले के कई बयानों के बीच कुछ छोटे और गैर-महत्वपूर्ण विरोधाभास किए हैं। प्रतिबद्ध कार्यवाही के तीन सेट थे, और निश्चित रूप से पुलिस द्वारा सामान्य पूछताछ और फिर सत्र न्यायालय में कार्यवाही, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इन साधारण देहाती लोगों को भ्रमित होना चाहिए और बारीकी से याद नहीं रखना चाहिए कि उन्होंने मंच से मंच तक क्या कहा था। लेकिन विभिन्न अदालतों में जिरह में उन्हें फंसाने के कई प्रयासों के बावजूद उनकी कहानी का बड़ा हिस्सा उल्लेखनीय रूप से एक साथ लटका हुआ है। जैसा कि जे. रेड्डी ने इन विसंगतियों को विस्तार से निपटाया है, हमें इस पर फिर से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

जाँच रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिखाई गई चोटें मेल नहीं खाती हैं। यह संदिग्ध है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत एक जांच रिपोर्ट कहाँ तक स्वीकार्य है, लेकिन हम इस अंतर को मुल्यवान रूप में नहीं मानते हैं जहाँ तक अपीलकर्ताओं का संबंध है; सबसे अच्छा यह केवल मदद कर सकता था पूछताछ रिपोर्ट आठ चोटों को दिखाती है। पहले चार घाव कटे हुए हैं और गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य से मेल खाते हैं। शेष चार "नीले और काले निशान" के रूप में वर्णित हैं। पोस्टमॉर्टम में पहले चार का उल्लेख है लेकिन अन्य का नहीं। उच्च न्यायालय द्वारा डॉक्टर को वापस बुला लिया गया था और वह शरीर पर पोस्टमॉर्टम के दाग के बारे में कुछ प्रकार का

स्पष्टीकरण देता है जो हमें संतोषजनक नहीं लगता है, लेकिन इससे पता चलता है कि शरीर पर कोई छड़ी नहीं लगी थी और हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अच्छी बात यह है कि यह केवल तुकाराम और नीलिया की मदद कर सकता था जिन्होंने अपील नहीं की है।

सबूतों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर हमें लगता है कि रसिका और सुभाना सच कह रहे हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है, हम अन्य दो गवाहों पर भरोसा नहीं करेंगे। हम रसिका और सुभाना के साक्ष्य की अवहेलना करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वे कहते हैं कि तुकाराम और नीलिया ने भी रामचंद्र को पीटा था क्योंकि चिकित्सा साक्ष्य किसी भी चोट का खुलासा नहीं करते हैं जो छड़ी या लाठी से हुई हो सकती है। वास्तव में सुभारिया ने तुकाराम या नीलिया को किसी विशेष प्रहार का श्रेय नहीं दिया है, हालांकि वह विस्तार से बताते हैं कि अन्य तीनों ने क्या किया। तुकाराम और नीलिया के बारे में वह बस इतना ही कहता है - "उपस्थित अभियुक्त रामचंद्र को मार रहे थे; पांडुरंग, भिलिया और तुकिया कुल्हाड़ी पकड़े हुए थे। तुकाराम और नीलिया के हाथों में डंडे थे। इस तरह के सर्वव्यापी आरोप का बहुत अधिक महत्व नहीं है, और रसिकाबाई बहुत बेहतर नहीं हैं, हालांकि वह कहती हैं कि नीलिया ने रामचंदर को जांघ पर मारा था। इसके अलावा, वह केवल इतना कहती है कि "हमने आरोपी को रामचंद्र शेल्के को मारते हुए देखा था।"हमें लगता है कि रसिका और सुभाना सच बोल रहे हैं जब वे कहते हैं कि ये दोनों आरोपी भी वहाँ थे, लेकिन हमें लगता है कि इसी वजह से उन्हें लगता है कि वे हमले में शामिल हुए होंगे और इसलिए उन्होंने अपनी कहानी में उस विवरण को जोड़ा है। यह भी संभव है कि नीलिया ने रामचंद्र पर प्रहार किया हो, लेकिन प्रहार उनके शरीर पर नहीं पड़ा हो। किसी भी मामले में, उनके हाथों में केवल डंडे थे जिन्हें लाठियों तुल्य नहीं माना गया है। इसलिए उन्होंने जो भूमिका निभाई वह नगण्य थी। हमने उनके मामलों को इस हद तक देखा है ताकि हम उन्हें यह निर्धारित

करने में एक तरफ रख सकें कि शेष चोटों के लिए कौन जिम्मेदार था और यह भी कि उन्होंने जो भूमिका निभाई वह सामान्य उद्देश्य या इरादे, यदि कोई हो, की सीमा निर्धारित करने में आवश्यक होगी। चिकित्सीय साक्ष्य से पता चलता है कि मौत का कारण गर्दन पर लगी चोट थी। सभी प्रत्यक्षदर्शी इस बात से सहमत हैं कि इसके लिए भीलिया जिम्मेदार थी। हम यहाँ अन्य चश्मदीद गवाहों का उल्लेख यह दिखाने के लिए करते हैं कि इस बिंदु पर कोई विसंगति नहीं है, लेकिन हम तथ्य को निर्धारित करने के लिए केवल रसिकाबाई और सुभाना पर भरोसा करते हैं। भीलिया पर सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाया गया था और आरोप में गले पर चोट के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया है। इसलिए उसकी दोषसिद्धि पर किसी भी तकनीकी मुद्दे पर हमला नहीं किया जा सकता है जो अन्य दो के मामले में उत्पन्न होते हैं। हम भारतीय दंड संहिता की धारा302 के तहत उसकी सजा को बरकरार रखते हैं।

गले की चोट का हिसाब लगा लिया गया है, हमारे पास तीन बचे हैं। वे हैं-(1) बाईं कार के ऊपर खोपड़ी पर एक कटा हुआ घाव, (2) खोपड़ी, मध्य भाग पर एक कटा हुआ घाव, और (3) चेहरे के बाईं ओर एक कटा हुआ घाव जो होंठ और दांत सहित ऊपरी और निचले जबड़ों को कुचल देता है। डॉक्टर का कहना है कि (1) और (2) मृत्यु का कारण नहीं हो सकते थे, लेकिन तीसरा हो सकता था। रसिकाबाई और सुभाना इस बात पर सहमत हैं कि गाल पर प्रहार करने वाला एकमात्र व्यक्ति तुकिया है। रसिकाबाई कहती हैं कि उन्होंने रामचंद्र के सिर पर भी वार किया था। इसका मतलब है कि तुकिया और पांडुरंग के सिर पर दो गैर-घातक चोटें आईं, एक-एक, और अकेले तुकिया के कारण गाल पर घातक चोट लगी। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा302 के तहत तुकिया को दोषी ठहराया जाना उचित था पांडुरंग के मामले में हमारे पास भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के बारे में कठिन प्रश्न रह गया है, इससे पहले कि हम इससे निपटें, हम भारतीय दंड संहिता की धारा 149 को अलग कर देंगे। धारा 149 के

तहत कोई आरोप नहीं है और, जैसा कि लॉर्ड समनर ने बरेंद्र कुमार घोष बनाम राजा-सम्राट (1) में बताया है, धारा 149, धारा 34 के विपरीत, एक विशिष्ट अपराध पैदा करती है और केवल उस अपराध की सजा से संबंधित है। तदनुसार हमें धारा 149 का उपयोग करने के लिए मजबूत कारणों की आवश्यकता होगी जब यह आरोप नहीं लगाया जाता है, भले ही किसी विशिष्ट आरोप के अभाव में उस धारा के तहत दोषी ठहराना संभव हो, एक बिंदु जिसे हम यहां तय नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा, हमारी राय में, यहाँ कोई सबूत नहीं है जो एक सामान्य उद्देश्य के निष्कर्ष को सही ठहराए, भले ही किसी पर आरोप लगाया गया हो।अब भले ही यह स्वीकार किया जाए कि यह साक्ष्य पूर्व नियोजित कार्यक्रम का संकेत है, लेकिन इसमें केवल तीन लंबाड़ा, नीलिया, भीलिया और तुकिया शामिल हैं। पांडुरंग, जो एक हाटकार है, शामिल नहीं है। चूँकि यह एकमात्र सबूत है जो एक सामान्य उद्देश्य का संकेत देता है, और जैसा कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते कि हमले से पहले क्या हुआ था (क्योंकि गवाह इसके शुरू होने के बाद पहुंचे थे), हम इस तथ्य से कोई सामान्य वस्तु एकत्र नहीं कर सकते हैं कि पांडुरंग ने कुल्हाड़ी से लैस होने के बावजूद, केवल खोपड़ी पर हल्का प्रहार किया, जिससे उस क्षेत्र की कोई भी नाजुक हड्डी नहीं टूटी और इस तथ्य से कि दो अन्य जो हल्के हथियारों से लैस थे, जिन्हें "लाठी" कहा जाता है, उन्होंने कोई चोट नहीं पहुंचाई। इसलिए धारा 149 का कोई सवाल ही नहीं है।

अब धारा 34 की ओर मुड़ते हुए, जिस पर पांडुरंग के मामले में आरोप नहीं लगाया गया था, लेकिन हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ऐसी चूक घातक है क्योंकि भले ही उस पर आरोप लगाया गया हो, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे उसे गले लगाने के सामान्य इरादे का वैध रूप से अनुमान लगाया जा सके। जैसा कि हमने अभी कहा है, गवाह ऐसे समय पर पहुंचे जब पिटाई पहले से ही चल रही थी। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था कि पहले क्या हुआ था। हम इस बात

से संतुष्ट नहीं हैं कि तुकाराम ने उपस्थित होने के अलावा कुछ भी किया था, और भले ही यह स्वीकार किया जाए कि नीलिया ने रामचंद्र की जांघ पर प्रहार किया था, वह इसके बारे में इतना आधा दिल था कि वह उसे चोट भी नहीं लगी; और पांडुरंग के मामले में, हालांकि एक घातक हथियार से लैस था, उसने तुलनात्मक रूप से सिर पर हल्की चोट लगाने के अलावा और कुछ नहीं किया। यह सच है कि जब प्रत्यक्षदर्शी आए तो वे सभी भाग गए और बाद में फरार हो गए, लेकिन इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि वे एक शव के रूप में एक साथ भाग गए, या कि वे बाद में मिले। रसिकाबाई का कहना है कि जब उसने उन्हें पुकारा तो "अभियुक्तों" ने अपनी कुल्हाड़ी और डंडे उठाए और उसे धमकी दी, लेकिन यह फिर से एक ऐसा बयान है जिसे हम आगे के विवरण के अभाव में शाब्दिक रूप से लेने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग आम तौर पर एक यूनानी समूह की तरह एकजुट होकर कार्य नहीं करते हैं और, बेईमानी के अलावा, यह उन गवाहों के साथ एक पसंदीदा उपकरण है जो या तो मानसिक रूप से सतर्क नहीं हैं या मानसिक रूप से आलसी हैं और शिथिल सोच के लिए दिए जाते हैं। वे अक्सर "सभी" कहने के लिए उपयुक्त होते हैं, तब भी जब वे केवल "कुछ" देखते हैं क्योंकि वे बहुत आलसी होते हैं, मानसिक रूप से, अंतर करने के लिए। इसलिए जब तक कोई गवाह यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि कब कई आरोपी हैं, तब तक इस तरह के सर्वव्यापी समावेशन को उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार करना आमतौर पर असुरक्षित है। हम इन तथ्यों से हत्या के लिए किसी भी पूर्व व्यवस्था का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं।

अब धारा 34 के मामले में हम सोचते हैं कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक सामान्य इरादा पूर्व नियोजित कार्यक्रम का अनुमान लगाता है। इसके लिए एक पूर्व-व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है क्योंकि इससे पहले कि किसी व्यक्ति को दूसरे के आपराधिक कृत्य के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दोषी ठहराया जा सके, यह कार्य

उन सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया होगाः महबूब शाह बनाम राजा-सम्राट (1)। तदनुसार विचारों का मेल होना चाहिए था कई व्यक्ति एक साथ एक व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं और प्रत्येक का एक ही इरादा हो सकता है, अर्थात् मारने का इरादा, और प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से एक अलग घातक प्रहार कर सकता है और फिर भी किसी का भी अनुभाग द्वारा आवश्यक सामान्य इरादा नहीं होगा क्योंकि पूर्व-निर्धारित योजना बनाने के लिए दिमाग की कोई पूर्व बैठक नहीं थी। इस तरह के मामले में, प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा की गई किसी भी चोट के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, लेकिन किसी को भी अन्य के किसी भी कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है; और यदि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सकता है कि उसका अलग प्रहार एक घातक था तो उसे हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, हालांकि स्पष्ट रूप से उसके मामले में मारने का इरादा साबित किया जा सकता हैः बरेंद्र कुमार घोष बनाम राजा सम्राट (2) और महबूब शाह बनाम राजा-सम्राट (1)। जैसा कि उनके अधिपति बाद के मामले में कहते हैं, "विभाजन जो उनकी सीमाओं को विभाजित करता है, अक्सर बहुत कम होता हैः फिर भी, अंतर वास्तविक और पर्याप्त है, और अगर अनदेखी की जाती है तो इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी।"

योजना को विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है, न ही लंबे समय के अंतराल की आवश्यकता है। यह अचानक उत्पन्न हो सकता है और अचानक बन सकता है, उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने में मदद करने के लिए राहगीरों को बुलाता है और वे, या तो अपने शब्दों या अपने कार्यों से, उसे अपनी सहमति का संकेत देते हैं और हमले में उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तब मस्तिश्को के मिलन की आवश्यक्ता होती है। एक पूर्व-व्यवस्थित योजना है, हालांकि जल्दबाजी में बनाई गई और अशिष्ट रूप से कल्पना की गई। लेकिन पूर्व-व्यवस्था और पूर्व नियोजित

संगीत कार्यक्रम होना चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है, जैसा कि बाद के प्रिवी काउंसिल मामले में, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से एक ही इरादा रखना, उदाहरण के लिए, दूसरे को बचाने का इरादा और यदि आवश्यक हो, तो विरोध करने वालों को मारना। वर्तमान मामले में, किसी भी पूर्व बैठक का कोई सबूत नहीं है। हम इस बारे में कुछ नहीं जानते कि उन्होंने हमले से पहले क्या कहा या क्या किया-तुरंत पहले भी नहीं। पांडुरंग दूसरों के समान जाति का भी नहीं है।

भिलिया, तुकिया और नीलिया लम्बादास हैं, पांडुरंग हाटकार हैं और तुकाराम मराठा हैं। यह सच है कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम और व्यवस्था को बाद के आचरण से निर्धारित किया जा सकता है, और वास्तव में अक्सर किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, कार्रवाई के दौरान खुद को प्रकट करने वाले अभियान की एक व्यवस्थित योजना द्वारा, जिसे केवल पूर्व नियोजित कार्यक्रम और पूर्व-व्यवस्था के लिए संदर्भित किया जा सकता है, या एक निकाय में एक साथ भागना या बाद में एक साथ एक बैठक। लेकिन, प्रिवी काउंसिल को फिर से उद्धृत करने के लिए, "सामान्य इरादे के निष्कर्ष को तब तक नहीं सिखाया जाना चाहिए जब तक कि यह मामले की परिस्थितियों से अनुमानित एक आवश्यक निष्कर्ष न हो।"

लेकिन यह कहना परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में सामान्य नियम को दोहराने से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इस वर्ग के मामले के लिए साक्ष्य का कोई विशेष नियम नहीं है। अंत में, यह हर मामले में तथ्य का सवाल है और परिस्थितियों के समान होने के बावजूद, एक मामले में तथ्यों का उपयोग दूसरे मामले में तथ्यों पर निष्कर्ष निर्धारित करने के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं किया जा सकता है। केवल इतना आवश्यक है कि या तो पूर्व संयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण हो, या उन परिस्थितियों का प्रमाण हो जो आवश्यक रूप से उस निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं, या जैसा कि हम इसे समय-सम्मानित तरीके से रखना पसंद करते हैं, "दोषपूर्ण तथ्यों को अभियुक्त की

निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए और किसी अन्य उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए।" (सरकार का साक्ष्य, 8 वां संस्करण, पृष्ठ 30)। राज्य के विद्वान वकील ने मामंद बनाम सम्राट (1) पर भरोसा किया क्योंकि उस मामले में सभी आरोपी भाग गए और उनके एक सामान्य इरादे को स्थापित करने के लिए इसे ध्यान में रखा। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ था। अभियुक्त की ओर से दुश्मनी का सबूत था जो केवल हमले में शामिल हुआ था, लेकिन हत्या में उसका कोई हाथ नहीं था, और वास्तविक हत्या करने वाले दोनों की ओर से कोई नहीं था। इस बात के प्रमाण थे कि तीनों एक साथ रहते थे और एक छोटा भाई था और दूसरा विचाराधीन अपीलार्थी का किरायेदार था। इस बात के प्रमाण थे कि वे सभी एक साथ भाग गए थेः केवल यह नहीं कि पता चलने पर वे एक ही समय पर भाग गए, बल्कि यह कि वे एक साथ भाग गए।

जैसा कि हमने कहा है, प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और एक मामले में तथ्यों की केवल समानता का उपयोग दूसरे मामले में तथ्य के निष्कर्ष को निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, हमारी राय है कि प्रकट किए गए तथ्य पांडुरंग के मामले में सामान्य इरादे के निष्कर्ष की गारंटी नहीं देते हैं। इसलिए, भले ही उस पर आरोप लगाया गया हो, उस आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती थी। तदनुसार पांडुरंग केवल वही करता है जो उसने वास्तव में किया था। हमारी राय में, उसका कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत आता है। कुल्हाड़ी से सिर पर प्रहार जो सिर में आधा इंच घुस जाता है, हमारी राय में, जीवन को खतरे में डालने की संभावना है। इसलिए हम भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के तहत उसकी दोषसिद्धि को दरकिनार करते हैं और इसके बजाय उसे धारा 326 के तहत दोषी ठहराते हैं। हमारी राय है कि उसके मामले में दस साल की अवधि

के लिए कारावास की सजा पर्याप्त होगी। हम तदनुसार मौत की सजा को अलग करते हैं और इसे दस साल के कठोर कारावास में से एक में बदल देते हैं।

यह भीलिया और तुकिया के मामले में सजा का सवाल छोड़ देता है। यह तर्क दिया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 के कारण दो न्यायाधीश सहमत हैं और यह तर्क दिया गया था कि संहिता की धारा 378 उस प्रावधान को निरस्त या संशोधित नहीं करती है। हम यहां इसकी जांच करने का इरादा नहीं रखते हैं क्योंकि हमारी राय है कि इन दोनों मामलों में सजा को मुख्य रूप से उच्च न्यायालय में न केवल अपराध के सवाल पर, बल्कि सजा के सवाल पर भी मतभेद के कारण कम किया जाना चाहिए। यह कहते हुए हम इस मामले में न्यायाधीशों के विवेक को बाधित करने का इरादा नहीं रखते हैं, क्योंकि सजा का प्रश्न विवेक का विषय है और हमेशा बना रहना चाहिए, जब तक कि कानून अन्यथा निर्देश न दे। लेकिन जब अपीलीय न्यायाधीश, जो अपराध के सवाल पर सहमत होते हैं, सजा के बारे में भिन्न होते हैं, तो आम तौर पर मृत्युदंड नहीं दिया जाता है जब तक कि कोई ठोस कारण न हों। हम इस मामले में इस प्रथा से हटने का कोई कारण नहीं देखते हैं और इसलिए उच्च न्यायालय में मतभेद के कारण भीलिया और तुकिया के मामले में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।